पटना, जागरण ब्यूरो : बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरक्की के रास्ते खुल गये हैं। सरकार द्वारा प्रोन्नति के लिए कालावधि की मियाद घटा देने के कारण धड़ाधड़ प्रोन्नति मिल रही है। बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के बाद इस सेवा के लोगों को मौजूदा से एक रैंक ऊपर में समायोजन किया गया। मगर वरीय पद पर रिटायरमेंट की रफ्तार और रिक्त होने वाली सीटों को तत्काल भरने के मकसद से सरकार ने कालावधि एक साल से घटाकर छह माह कर दिया। नतीजा है कि छह महीने में ही दो-दो तरक्की मिल रही है। पुनर्गठन के कारण निचले स्तर के पदों पर तरक्की में आयी स्थिरता (स्टेगनेशन) पर भी विराम लगा है। जल्द ही बिहार प्रशासनिक सेवा के अनेक अधिकारी तरक्की पायेंगे। अगले पद पर प्रोन्नति के लिए जरूरी है कि मौजूदा पद पर आपने निर्धारित वर्ष तक सेवा की हो। मगर विलंब से प्रोन्नति के कारण यह मियाद आगे की प्रोन्नति में बाधक बन रहा था। इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 2007 में ही कालावधि की गणना में राहत दी। तय किया गया कि न्यूनतम कालावधि पूरी न होने के कारण जहां प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पाता वहां धारित पद एवं ऊसके एक स्तर नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों-वेतनमानों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक साल का अनुभव पूरा हो जाता है कि ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। इस प्रावधान से लोगों को राहत मिली। मगर पिछले साल बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के बाद विशेष सचिव में 24 पद मिल गये, अपर सचिव के पदों में भी काफी वृद्धि हो गयी। लेकिन विशेष सचिव बने बड़ी संख्या में लोग रिटायर करने लगे। इस साल करीब 20-22 लोग रिटायर करने वाले हैं। नतीजतन कालावधि के संकट को देखते हुए सरकार ने इसी माह प्रोन्नति के लिए मौजूदा पद पर काम की मियाद को एक साल से घटाकर छह माह कर दी। गुरुवार को ही कैबिनेट से इसके अनुपालन में अपर सचिव से विशेष सचिव में 7 अधिकारियों को तरक्की दे दी और 15 अधिकारियों का पैनल तैयार कर दिया। अपर

सचिव में जल्द रिटायर करने वालों की संख्या शामिल कर दें तो अपर सचिव में 26-27 सीटें खाली हो रही हैं। अपर सचिव के पद भरेंगे तो संयुक्त सचिव में रिक्ति होगी। चार साल के बैकलाग में 59 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस बनने वाले हैं। ऐसे में इतनी रिक्तियां और हो जायेंगी। स्वाभाविक तौर पर नीचे के अधिकारियों की तरक्की का रास्ता साफ हो रहा है और यह जल्द होगा। अड़चन कम रहे इसके लिए पैनल तैयार रखने की तैयारी है। बिहार प्रशासनिक सेवा में तरक्की की बाधा खत्म

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति